

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(Railway Board/रेलवे बोर्ड)

S.No.PC-VI/397
No. PC-V/2010/A/TA/1

RBE No. 138/2019
New Delhi, dated 21-08-2019

The General Manager/CAO(R)
All Zonal Railways & PUs
(As per mailing list)

Sub:-Grant of Transport Allowance @Rs.7000/-p.m. +DA thereon to the IRMS officers drawing Grade Pay of Rs.10,000/- under DACP Scheme.

Attention is invited to Board's letter of even number dated 25-08-2015 whereby Railways were advised to keep in abeyance the payment of Transport Allowance @ Rs.7000/-p.m. + DA thereon to IRMS officers drawing Grade Pay of Rs.10,000/- under DACP Scheme. Subsequently, as per the interim order dated 27-10-2015 of Hon'ble CAT/New Delhi in O.A No. 3528/2015, Railways were advised vide this office letter of even number dated 06-11-2015 that the payment of Transport Allowance to IRMS officers @Rs.7000/-p.m. + DA thereon, be continued till further orders.

2. The Hon'ble CAT/New Delhi vide order dated 28-05-2019 has now disposed of the said O.A No. 3528/2015 has observed as under :-

"The OA is, therefore, disposed of, directing the respondents to take a final decision regarding extension or otherwise of the Transport Allowance at the rate of Rs.7000/- per month plus DA, to the members of the applicant Association, within a period of three months from the receipt of this order. However, the amount already paid towards the said allowance shall not be recovered, and the respondents shall not be under an obligation to pay the said allowance until a final decision is taken. There shall be no orders as to costs."

3. The matter has been accordingly considered by the competent authority and in view of fact that IRMS officers drawing Grade Pay of Rs.10,000/- (now pay level -14) under DACPS except those who are holding pinpointed administrative SAG posts mentioned in Board's letter No. 2009/H/16/1DACP dated 26-02-2009, are not entitled for use of official car in terms of Board's letter No. E(G)95AL4-9, dated 06-11-1995, it has been decided that such officer shall not be eligible to opt for higher rate of Transport Allowance @Rs.7000/-p.m.+DA thereon (which now stands revised to Rs.15750/-p.m.+DA thereon based on the recommendations of the 7th CPC). These officers are entitled for Transport Allowance @Rs.7200/3600 + D.A thereon as per row- 2 of Board's letter of even number dated 3-8-2017.

4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board.
5. Hindi version will follow.



Subhankar Dutta)
Dy. Director, Pay Commission-5
Railway Board

No. PC-V/2010/A/TA/1

New Delhi, dated 21-8-2019

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.



for Financial Commissioner, Railways

No. PC-V/2010/A/TA/1

New Delhi, dated 21-8-2019

Copy forwarded to:-

- 1) The General Secretary, NFIR, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 35 spares)
- 2) The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhavan, New Delhi (with 35 spares)
- 3) The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares)
- 4) The Secretary General FROA
- 5) The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association
- 6) The President, Railway Board Group 'B' Officers' Association
- 7) The Secretary General, All India RPF Association
- 8) The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association
- 9) The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association
- 10) Railway Board Promottee Officers Association, Room No, 341-C, Rail Bhawan.
- 11) Secretary General, Indian Rly. Promottee Officers Federation, Room No.268, Rail Bhawan.
- 12) President, RBSS Group 'A' Officer Association, Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.



for Secretary, Railway Board

Copy to:-

1. The GMs, N.F. Railway (Const.), CAO, SR (Const.) and CR (Const.)
2. PFA, All Indian Railways, PUs, NFR (Const.), SR (Const.) & CR (Const.)
3. The Director General, RDSO, Lucknow
4. The General Manager and FA & CAO, Metro Railway/Calcutta
5. The CAO and FA & CAO, COFMOW/New Delhi
6. The General Manager and FA & CAO, CORE/Allahabad
7. The Director General, Railway Staff College/Vadodara
8. The CAO (Const.), MTP(R)/Mumbai

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

क्र. सं. पीसी-VII/397
सं. पीसी-V/2010/ए/टीए/1

आरबीई सं. / 38 /2019
नई दिल्ली, दिनांक 21.08.2019

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर)
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां,
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: रु. 10,000/- ग्रेड पे लेने वाले आईआरएमएस अधिकारियों को डीएसीपी योजना के तहत प्रति माह
रु. 7000/- + इस पर महंगाई भत्ता की दर से परिवहन भत्ता देना।

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 25.08.2015 के समसंख्यक पत्र की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा रेलों को सुझाव दिया गया था कि रु. 10,000/- ग्रेड पे लेने वाले आईआरएमएस अधिकारियों को डीएसीपी योजना के तहत प्रति माह रु. 7000/- + इस पर महंगाई भत्ता की दर से परिवहन भत्ते का भुगतान प्रास्थगित कर दिया जाए। तदन्तर, माननीय कैट/नई दिल्ली के दिनांक 27.10.2015 के ओ. ए. नं. 3528/2015 के अंतरिम आदेश के अनुसार, रेलों को इस कार्यालय के दिनांक 06.11.2015 के समसंख्यक पत्र के तहत सुझाव दिया गया था कि आईआरएमएस अधिकारियों को प्रति माह रु. 7000/- + इस पर महंगाई भत्ते की दर से अगले आदेश तक परिवहन भत्ता देना जारी रखा जाए।

2. माननीय कैट/नई दिल्ली ने दिनांक 28.05.2019 के आदेश के तहत निम्नलिखित अवलोकन के साथ ओ.ए. संख्या 3528/2015 का निपटान कर दिया है:

“अतः, आवेदक संघ के सदस्यों को प्रति माह रु. 7000/- + महंगाई भत्ते की दर से परिवहन भत्ता देने या अन्य प्रकार से भुगतान करने के संबंध में यह आदेश प्राप्त होने के तीन माह की अवधि के भीतर अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए इस ओ.ए. का निपटान किया जाता है। बहरहाल, उक्त भत्ते के तहत पहले से भुगतान की गई राशि वसूल नहीं की जाएगी और जब तक अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक प्रतिवादी उक्त भत्ते का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। मुकदमे की फीस से संबंधित कोई आदेश नहीं होगा।”

3. तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन अधिकारियों, जो बोर्ड के दिनांक 26.02.2009 के पत्र सं. 2009/एच/16/1डीएसीपी में

उल्लिखित सबसे छोटे प्रशासनिक एसएजी पद पर हैं, को छोड़कर रु. 10,000/- (अब पे लेवल -14) प्राप्त करने वाले आईआरएसएस के शेष अधिकारी बोर्ड के दिनांक 06.11.1995 के पत्र सं. ई(जी)95एएल4-9 के अनुसार डीएसीपीएस के अंतर्गत सरकारी कार का उपयोग करने के हकदार नहीं हैं, यह विनिश्चय किया गया है कि वे अधिकारी प्रति माह रु. 7000/- + उस पर महंगाई भत्ते (जिसे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अब संशोधित करके प्रति माह रु. 15750/- + उसपर महंगाई भत्ता कर दिया गया है) की दर से उच्च दर पर परिवहन भत्ता लेने के पात्र नहीं होंगे। ये अधिकारी बोर्ड के दिनांक 3.8.2017के समसंख्यक पत्र की पंक्ति-2 के अनुसार, रु. 7200/3600 + महंगाई भत्ता की दर से परिवहन भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं।

4. इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।



(शुभंकर दत्ता)

उप निदेशक, वेतन आयोग-5
रेलवे बोर्ड